

मुद्दा/विश्लेषण	Application/Value Add/ Think
विषय: सीबीआई निदेशक की नियुक्ति	GS-III-आंतरिक सुरक्षा GS-II- शासन
कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद अगले सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) निदेशक होंगे।	
<p><b>केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बारे में:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) द्वारा CBI की स्थापना की सिफारिश की गई थी।</li> <li>• CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसे गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव (1963) द्वारा स्थापित किया गया था।</li> <li>• यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।</li> <li>• केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) केंद्र सरकार की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है।</li> <li>• भ्रष्टाचार की रोकथाम और प्रशासन में ईमानदारी बनाए रखने में CBI महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है।</li> <li>• नोडल मंत्रालय: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय;</li> <li>• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए, सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग को अधीक्षण सौंपती है।</li> </ul>	सीबीआई भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है।
<p><b>सीबीआई निदेशक की नियुक्ति:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है। उन्हें एक विशेष/अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।</li> <li>• केंद्र सरकार तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर CBI के निदेशक की नियुक्ति करेगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शामिल होंगे।</li> <li>• जब लोकसभा में कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता उस समिति का सदस्य होगा।</li> <li>• सीबीआई के निदेशक को मुख्य सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा कार्यालय में दो साल के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है।</li> </ul>	
<p><b>सीबीआई पर कुछ आम आलोचनाएं इस प्रकार हैं:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>सत्ताधारी पार्टी का राजनीतिक उपकरण:</b> आलोचकों का तर्क है कि सत्ताधारी सरकार द्वारा एजेंसी को अक्सर राजनीतिक विरोधियों को लक्षित करने या सत्ता में बैठे लोगों को जांच से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों को संभालने में इसके कथित पूर्वाग्रह के कारण एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है।</li> </ul>	<p>सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह ने अपनी बुक में एजेंसी के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद (nepotism) के बारे में खुलासा किया है।</p> <p>2019 में, एजेंसी अपने निदेशक और उसके विशेष निदेशक के बीच रस्साकशी (turf</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>जांच की धीमी गति:</b> जांच करने और न्याय देने में धीमी गति के लिए सीबीआई की आलोचना की गई है। जांच पूरी करने और मुकदमा चलाने में देरी से जनता का विश्वास कम हुआ है।</li> <li>● <b>अपर्याप्त संसाधन और कर्मचारी:</b> एजेंसी पर काम का बोझ बहुत अधिक है, और यह मामलों की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ रही है। कुशल जांचकर्ताओं, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और आधुनिक तकनीक की कमी इसकी जांच क्षमताओं को बाधित करती है।</li> <li>● <b>पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी:</b> मनमाना निर्णय लेने, चुनिंदा सूचनाओं के लीक होने और एजेंसी के कार्यों में जवाबदेही की कमी के आरोप लगे हैं। आंतरिक और बाहरी निरीक्षण के लिए एक व्यापक तंत्र की कमी ने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंता जताई है।</li> <li>● <b>राजनीतिक दबाव और प्रभाव:</b> सीबीआई को राजनीतिक दबाव और प्रभाव के सामने झुकने के आरोपों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों या राजनीतिक दलों से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों में। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां राजनीतिक विचारों के कारण जांच को कथित रूप से पटरी से उतार दिया गया या समझौता कर लिया गया, जिससे एजेंसी की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा पर सवाल उठने लगे।</li> <li>● <b>सार्वजनिक आउटरीच और संचार की कमी:</b> सीमित सार्वजनिक पहुंच और संचार के लिए सीबीआई की आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए एजेंसी को अपनी जांच और परिणामों के बारे में जानकारी साझा करने में अधिक पारदर्शी होना चाहिए।</li> </ul>	<p>war) में शामिल थी। दोनों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे।</p>
<p>आलोचनाओं को दूर करने और भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के कामकाज में सुधार के लिए कई उपायों पर विचार किया जा सकता है। आगे बढ़ने के कुछ संभावित तरीके यहां दिए गए हैं-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>बढ़ी हुई स्वायत्तता:</b> सीबीआई को अधिक स्वायत्तता और राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रखा जाना चाहिए।</li> <li>● <b>संसाधनों और क्षमता को मजबूत करना:</b> सीबीआई को संसाधनों, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के मामले में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।</li> <li>● <b>जांच प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:</b> सीबीआई को जांच की दक्षता और समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए अपनी जांच प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए।</li> <li>● <b>जवाबदेही और निरीक्षण तंत्र:</b> पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक और बाहरी निरीक्षण के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना महत्वपूर्ण है। सीबीआई के कार्यों की निगरानी करने, उसके प्रदर्शन की समीक्षा करने और कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए स्वतंत्र निकायों या तंत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए।</li> </ul>	<p>निष्कर्ष</p>

मुद्दा/विश्लेषण	Application/Value Add/ Think
<b>विषय: भारत में डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध</b>	GS-III- पर्यावरण संरक्षण GS-III- सतत अर्थव्यवस्था GS-II- शासन
<p>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल ने 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में 2027 तक डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने तथा इसके बजाय इलेक्ट्रिक और गैस-ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● पैनल की सिफारिशों ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और अपने 2070 के शुद्ध शून्य लक्ष्य के हिस्से के रूप में अक्षय ऊर्जा से 40% बिजली का उत्पादन करने के सरकार के घोषित उद्देश्य के मद्देनजर आती हैं।</li> <li>● डीजल वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का लगभग 40% हिस्सा है।</li> <li>● प्रस्तावित प्रतिबंध का एक महत्वपूर्ण पदचिह्न होगा - भारत में बड़ी संख्या में शहरों में 1 मिलियन से अधिक लोग हैं, और इसमें न केवल महानगरीय केंद्र शामिल हैं, बल्कि कोटा, रायपुर, धनबाद, विजयवाड़ा, जोधपुर, और अमृतसर जैसे छोटे शहर और शहर भी शामिल हैं।</li> <li>● 2020 के बाद से, अधिकांश कार निर्माताओं ने अपने डीजल पोर्टफोलियो को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नतीजतन, कुल डीजल वाहनों की मांग में यात्री वाहनों का योगदान 2013 में 28.5% की तुलना में घटकर महज 16.5% रह गया है। उदाहरण के लिए: देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 1 अप्रैल, 2020 से डीजल वाहन बनाना बंद कर दिया है।</li> </ul>	
<b>डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में तर्क</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>पर्यावरणीय लाभ:</b> डीजल वाहनों को उच्च स्तर के वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन करने के लिए जाना जाता है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर (PM), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO<sub>x</sub>) और हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों शामिल हैं। डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध से वायु प्रदूषण में काफी कमी आ सकती है, वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है।</li> <li>● <b>जलवायु परिवर्तन को कम करना:</b> डीजल वाहनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके, भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकता है और जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान कर सकता है।</li> <li>● <b>स्वास्थ्य और सुरक्षा:</b> डीजल उत्सर्जन में ऐसे प्रदूषक होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है।</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ऊर्जा सुरक्षा:</b> भारत में मुख्य रूप से डीजल का आयात किया जाता है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है। डीजल वाहनों से दूर जाने से जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और टिकाऊ परिवहन विकल्पों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।</li> <li>● <b>इलेक्ट्रिक और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना:</b> डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) और अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने में मदद मिल सकती है।</li> <li>● <b>सतत शहरी परिवहन को प्रोत्साहित करना:</b> डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाने और पैदल चलने सहित स्थायी शहरी परिवहन प्रणालियों की ओर बदलाव हो सकता है।</li> <li>● डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करना पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और देश को वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।</li> </ul>	
<p><b>डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ तर्क</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>आर्थिक प्रभाव:</b> डीजल वाहन, विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहन जैसे ट्रक और बसें, भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध के महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, जिनमें नौकरी का नुकसान, डीजल वाहनों पर निर्भर उद्योगों में व्यवधान और वैकल्पिक तकनीकों को अपनाने में चुनौतियां शामिल हैं।</li> <li>● <b>सामर्थ्य और पहुंच:</b> डीजल वाहन अक्सर अपने इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड समकक्षों की तुलना में अधिक किफायती होते हैं, जिससे वे आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ हो जाते हैं। डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध उन व्यक्तियों के लिए परिवहन विकल्पों को सीमित कर सकता है जो अपनी आजीविका या दैनिक आने-जाने की जरूरतों के लिए डीजल से चलने वाले वाहनों पर निर्भर हैं।</li> <li>● <b>इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां:</b> डीजल वाहनों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) को व्यापक रूप से अपनाने के लिए एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। भारत के कई हिस्सों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ईवी के बढ़ावा देने में बाधा बन सकती है।</li> <li>● <b>तकनीकी सीमाएं:</b> इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकियां अभी भी विकसित हो रही हैं, और बाजार वर्तमान में कुछ प्रकार के डीजल वाहनों के लिए व्यवहार्य विकल्प प्रदान नहीं कर सकता है, जैसे हेवी-ड्यूटी ट्रक या निर्माण और कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी।</li> <li>● <b>BS-VI नॉर्म्स में निवेश:</b> कई ऑटो उद्योग के खिलाड़ियों का तर्क है कि डीजल सेगमेंट में मौजूद कार निर्माता पहले से ही मौजूदा उत्सर्जन मानदंडों का</li> </ul>	<p>लगभग 87% डीजल ईंधन की बिक्री परिवहन खंड में होती है, जिसमें ट्रकों और बसों का लगभग 68% हिस्सा होता है।</p>

<p>अनुपालन कर रहे हैं, और उन्होंने अपने डीजल बेड़े को BS-IV से BS-VI उत्सर्जन मानदंडों में बदलने के लिए भारी निवेश किया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>इक्विटी और सामाजिक प्रभाव:</b> डीजल वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से आबादी के निम्न-आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो किफायती डीजल वाहनों पर निर्भर हैं।</li> </ul>	
<p>तत्काल पूर्ण प्रतिबंध के बजाय, एक लंबे चरणबद्ध परिवर्तन को लागू किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण उद्योगों और व्यक्तियों को अनुकूलन के लिए समय प्रदान करता है, जबकि स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित भी करता है।</p>	<p><b>निष्कर्ष</b></p>
<p><b>क्या आप जानते हैं?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● डीजल इंजन उच्च-वोल्टेज स्पार्क इग्निशन (स्पार्क प्लग) का उपयोग नहीं करते हैं, और इस प्रकार प्रति किलोमीटर कम ईंधन का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनका संपीड़न अनुपात अधिक होता है, जिससे यह भारी वाहनों के लिए पसंद का ईंधन बन जाता है।</li> <li>● इसके अलावा, डीजल इंजन अधिक टॉर्क (घूर्णी या टर्निंग बल) प्रदान करते हैं, और उनके स्टाल होने की संभावना कम होती है क्योंकि वे एक यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिससे दुलाई के लिए बेहतर साबित होते हैं।</li> </ul>	